अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

लोकसभा चुनाव (2024) में भाजपा और गठबंधन को प्राप्त जनादेश – एक समीक्षा

मिथिलेश कुमार माहथा
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड
ईमेल– mithileshkumarmahatha@gmail.com

सांराश (Abstract)

भारत में बहुदलीय प्रणाली है। यहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। भाजपा वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर शासन कर रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने के पूर्व 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल–जून 2024 में हुआ था, जिसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने केंद्र सरकार बनाई और श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। 26 विपक्षी दलों से मिलकर बने भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का गठन 2023 में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर भी अपने नये और पुराने सहयोगी राजनीतिक दलों को मिलाकर केन्द्र गठबंधन की सरकार बनायी। श्री नरेन्द्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सत्तारूढ हुए।

मूल शब्द : सरकार, बहुदलीय, भाजपा, कॉग्रेस, लोकसभा, चुनाव, गठबंधन

विषय प्रवेश : भारत में लोकसभा के सभी 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक सात चरणों में आम चुनाव हुए।[1] 4 जून, 2024 को मतगणना हुई तथा इसके परिणाम घोषित हुए, और 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। 7 जून, 2024 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 293 सांसदों के समर्थन की पुष्टि की । यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल था और पहली बार उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। इस गठबंधन में आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की जनता दल (यूनाइटेड) दो मुख्य सहयोगी के रूप में उभरीं।[2] यह अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसने पिछले चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया। यह चुनाव 44 दिनों तक चला, जो केवल 1951–52 के भारतीय आम चुनाव के बाद दूसरे स्थान पर था। आंध्र प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश , ओडिशा और सिक्किम राज्यों में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ–साथ 12 विधानसभाओं में 25 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों के साथ आयोजित किए गए थे। मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया, लगातार तीसरी बार चुनाव लड़े। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2014 और 2019 के चुनावों की अपेक्षा पूर्ण बहुमत से कम 272 सीटें प्राप्त हुई थीं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

गठबंधन (इंडिया) था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और कई क्षेत्रीय दलों द्वारा 2023 में गठित एक गठबंधन था। मीडिया आउटलेट्स के जनमत सर्वेक्षणों में भाजपा और उसके गठबंधन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की निर्णायक जीत का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जो 2019 में हासिल की गई 303 सीटों से कम थीं, और लोकसभा में अपना एकल बहुमत खो दिया। एनडीए ने सदन की 543 सीटों में से कुल 293 सीटें जीतीं। , इंडिया गठबंधन ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें हासिल कीं, जिनमें से 99 सीटें कांग्रेस ने जीतीं, जिससे पार्टी को 10 वर्षों में पहली बार आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिला।[3] इस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति में सुधार कर पायी है।

लोकसभा चुनाव एवं मतदान कार्यक्रम — भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च, 2024 को की गई थी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा के कारण 3 जून, 2024 को एक–एक बूथ पर पुनर्मतदान हुए। मध्य प्रदेश के बेतूलमें मतदान उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 26 अप्रैल 2024 (चरण 2) से 7 मई, 2024 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। मौसम की स्थिति के कारण जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग–राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुए थे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने के पूर्व 18वीं लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम इस प्रकार थे–

तालिका

मतदान कार्यक्रम	चरण						
	1	2	3	4	5	6	7
अधिसूचना दिनांक	20 मार्च	28 मार्च	12 अप्रैल	18अप्रैल	26 अप्रैल	29 अप्रैल	7मई
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि	27 मार्च	4 अप्रैल	19अप्रैल	25अप्रैल	3मई	6मई	14मई
नामांकन की जांच	28 मार्च	5अप्रैल	20अप्रैल	26अप्रैल	4मई	7मई	15मई
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	30 मार्च	8अप्रैल	22अप्रैल	29अप्रैल	6मई	9मई	17मई
मतदान की तिथि	19अप्रैल	26अप्रैल	7मई	13मई	20मई	25मई	1जून
मतों की गिनती की तिथि	4 जून 2024						
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	101½[b]	87½[b]	94	96	49	58	57

स्रोत[4]: http//eci.gov.in

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन — वर्ष 2024 के भारतीय आम चुनावों से पहले भारत की राजनीति तेजी से द्विध्रुवीय हो गई, जिसमें दो प्रमुख गठबंधन उभरे। सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया)। वर्ष 2024 के भारतीय लोकसभा चुनावों में छह राष्ट्रीय दलों ने चुनाव लड़ा भाजपा, भारतीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), राष्ट्रीय जन पार्टी (एनपीपी) और आम आदमी पार्टी (आप)। बीएसपी को छोड़कर बाकी सभी दल इन दोनों गठबंधनों में से किसी एक का हिस्सा थे। राष्ट्रीय दलों के अलावा, क्षेत्रीय दलों (जिन्हें निश्चित चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं) और अन्य गैर–मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा। एनडीए एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन है, जिसमें ज्यादातर मध्य–दक्षिणपंथी से लेकर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दल शामिल हैं। इसका नेतृत्व भाजपा करती है।

दल	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया		जीती गई सीटें	
भारतीय जनता पार्टी	उत्तर प्रदेश	75[54]	441[55]	30	240
कुल		541		293	

स्रोत[5] — ई पेपर प्रभात खबर

<u>लोकसभा चुनाव में उभरती प्रवृत्तियाँ और चुनावी मुद्दे</u> : वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के कई मुद्दे थे जिससे भारतीय मतदाता प्रभावित होकर अपना मतदान किये।

(क) श्रीराम मंदिर के अभिषेक समारोह और सांप्रदायिकता — भाजपा ने श्रीराम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रमों के लिए एक पर्चा तैयार किया ताकि देशभर के परिवारों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के अभिषेक के बाद, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं का एक नया युग हावी हो गया है। मोदी ने श्रीराम मंदिर के पुनर्निर्माण के अपने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वादे को पूरा किया और देश की हिंदू आबादी के प्रति भाजपा के घोषणापत्र को साकार करते हुए देखे गए। मोदी और भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को हिंदू समुदाय के सदस्यों से भी पर्याप्त समर्थन मिला है। साथ ही, बॉलीवुड की ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिनमें मोदी सरकार की नीतियों और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं का समर्थन किया गया है। ऐसी चिंताओं के जवाब में, भाजपा ने खतरे की आशंका के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि पार्टी इसे बदलने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब विपक्षी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने राम मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण करके इसे 'भाजपा–आरएसएस का कार्यक्रम' बना दिया गया

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि, यह निमंत्रण कांग्रेस के लिए अपने पाप को कम करने का अवसर था। इतिहास इसे 'हिंदू विरोधी' के रूप में ही आंकता रहेगा।[6] चारों शंकराचार्यों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका भी कहना था कि इस समारोह का राजनीतिकरण करके इस आधे–अधूरे बने मंदिर में एक चुनावी अभियान का हिस्सा बना दिया गया है। 21 अप्रैल को राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय संपदा में मुसलमानों की पहुँच को प्राथमिकता देने और सत्ता में आने के बाद संसाधनों को ''अधिक बच्चे पैदा करने वालों'' और ''घुसपैठियों'' में बाँटने की योजना बनाने का आरोप लगाया।[7] यह आरोप मुसलमानों की अधिक संख्या में प्रजनन करने की रूढ़ियों और भाजपा द्वारा प्रचारित उन षड्यंत्र सिद्धांतों को दर्शाता है कि मुसलमान हिंदुओं से अधिक होने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गे ने मोदी की टिप्पणियों को दहशत से भरा ''घृणास्पद भाषण'' और चुनाव के पहले चरण में भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विपक्ष से ध्यान हटाने की एक चाल बताया।[8] वहीं, राजस्थान के अधिकारियों को आज़ाद अधिकार सेना और एक गैर–लाभकारी संगठन से मोदी की गिरफ्तारी और उनके चुनाव प्रचार को निलंबित करने की मांग वाली शिकायतें मिलीं।

संविधान बचाओ नागरिक अभियान संगठन द्वारा भारत के चुनाव आयोग को लिखे गए एक शिकायत पत्र पर 17,400 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी ने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसका उद्देश्य न केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना था, बल्कि हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति घृणा को उकसाना और बढ़ाना भी था।

(ख) चुनावी ब्रांड – 15 फरवरी, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनावी चंदा प्रणाली, जिसे मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में शुरू किया था और जिसके तहत व्यक्ति और कंपनियां गुमनाम रूप से और बिना किसी सीमा के राजनीतिक दलों को धन दान कर सकती थीं, असंवैधानिक है।[9] न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया से दानदाताओं को नीति निर्माण पर प्रभाव डालने का अवसर मिलता है।18 मार्च, 2024 को न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 21 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी चंदा से संबंधित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया ताकि चुनावी दानदाताओं का उनके प्राप्तकर्ताओं से मिलान किया जा सके। न्यायालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ , भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ और संबद्ध वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों द्वारा दानदाताओं की पहचान उजागर करने की याचिका को खारिज कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि राजनीतिक दलों को दान देने वाले प्रमुख दानदाताओं में भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां जैसे वेदांता लिमिटेड, भारती एयरटेल, आरपीएसजी समूह और एस्सेल

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

माइनिंग शामिल थीं। इसमें यह भी पाया गया कि भाजपा को दर्ज किए गए सभी दान का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर, चुनावी बांड प्राप्त करने के मामले में शीर्ष पांच राजनीतिक दल भाजपा हैं, जिन्हें 6,060.5 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 1,609.5 करोड़ रुपये, कांग्रेस पार्टी को 1,421.8 करोड़ रुपये, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को 1,214.7 करोड़ रुपये और बीजू जनता दल (बीजेडी) को 775.5 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। चुनावी बांडों का सबसे बड़ा खरीदार तमिलनाडु स्थित लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख सैंटियागो मार्टिन पाए गए, जिन्होंने 2020 और 2024 के बीच 13.68 अरब रुपये (163 मिलियन डॉलर) के बांड खरीदे और टीएमसी, भाजपा और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) को दान दिया। किसी भी राजनीतिक दल को सबसे बड़ा एकल दानदाता मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) था, जो हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म है जिसने 2019 और 2024 के बीच 12 अरब रुपये (144 मिलियन डॉलर) से अधिक मूल्य के चुनावी बांड खरीदे और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), भाजपा और कांग्रेस पार्टी को दान दिया , जो उस दौरान तेलंगाना में बारी–बारी से सत्ता में थीं। विपक्ष के कुछ राजनेताओं ने चुनावी बांडों को ''घोटाला'' और ''जबरन वसूली रैकेट'' करार दिया है।[10] चुनावी बांडों से संबंधित आरोपों के जवाब में, भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि, उसके चुनावी बांड योग्यता के आधार पर प्राप्त किए गए थे। हालांकि, भारतीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि या तो भारतीय व्यवसायी नियमित रूप से रिश्वत देकर मुसीबतों से बच रहे हैं, या भाजपा–नियंत्रित सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनसे जबरन वसूली कर रही है। एसबीआई द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि कंपनियों ने बड़े सरकारी ठेके मिलने के समय के आसपास दान दिया था। शीर्ष 30 कॉर्पोरेट दानदाताओं में से लगभग आधे चुनावी बांड खरीदने के समय के आसपास सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच का सामना कर रहे थे।

(ग) वित्तपोषण संबंधी मुद्दे – 16 फरवरी, 2024 को, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग (आईटी) ने चल रहे कानूनी विवाद के तहत कांग्रेस पार्टी के 2.1 अरब रुपये (25.3 मिलियन डॉलर) वाले बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बाद में कहा कि कर अधिकारियों ने 13 फरवरी को 2.1 अरब रुपये (25 मिलियन डॉलर) का लोन लगाया, उसके बैंक खातों को लगभग सील कर दिया और 1.1 अरब रुपये (14 मिलियन डॉलर) जब्त कर लिए। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शिकायत की कि इन प्रतिबंधों के कारण पार्टी ठीक से चुनाव प्रचार करने में असमर्थ हो गई है, और कहा कि हमारी पूरी वित्तीय पहचान मिटा दी गई है। राहुल गांधी ने मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पार्टी के

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

खिलाफ ''आपराधिक कार्रवाई'' करने का भी आरोप लगाया, जिसे भाजपा ने नकार दिया।[11] पूर्व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी आरोप लगाया कि कर संबंधी मुद्दे पार्टी को ''पंगु बनाने के लिए किए जा रहे सुनियोजित प्रयासों'' का हिस्सा हैं।[12] सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एक अपील लंबित है। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उसने कांग्रेस से राजनीतिक दलों को कर भुगतान से छूट देने वाले कानून का उल्लंघन करने के लिए 135 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, न कि विपक्षी दल के दावों के विपरीत पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया है। पार्टी को 29 मार्च को आयकर विभाग से फिर से नोटिस मिला जिसमें उसे 1,823.08 करोड़ रुपये (216 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का भुगतान करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस ने भाजपा पर ''कर आतंकवाद'' में लिप्त होने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा आयकर कानूनों का गंभीर उल्लंघन कर रही है।[13] आयकर विभाग को ऐसे उल्लंघनों के लिए भाजपा से 4,617.58 करोड़ रुपये (546 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की मांग करनी चाहिए।

(घ) बेरोजगारी – बेरोजगारी का मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या रही है, और यह खासकर युवाओं को प्रभावित किया है। भारत में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। 2022 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी दर 23.2% थी, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी लगभग 7% थी। 2023 में, 42.3% स्नातक बेरोजगार थे, जो बढ़ती कार्यबल को समायोजित करने के लिए आवश्यक रोजगार वृद्धि की कमी को दर्शाता है। चुनाव प्रचार में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा बन गई, विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन ने बढ़ती मुद्रास्फीति, असमानता और बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की आलोचना की। अपने अलग युवा घोषणापत्र के हिस्से के रूप में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने सरकारी नौकरियों में 30 लाख रिक्तियों को भरने और ''शिक्षुता का अधिकार'' लाने का वादा किया।[14] जिसमें 25 वर्ष तक की आयु का कोई भी डिप्लोमा और डिग्री धारक एक वर्ष के लिए रोजगार की मांग कर सकता है और उसे नौकरी की अवधि के लिए 100,000 रुपये का एक वर्ष का वेतन मिलेगा। ,

(ङ) विवादास्पद बयान – लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान, कई राजनीतिक नेताओं ने विवादास्पद राजनीतिक टिप्पणियाँ कीं। सितंबर 2023 में, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की इस टिप्पणी के लिए आलोचना हुई कि सनातन धर्म का न केवल विरोध किया जाना चाहिए, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए।[15] उन्होंने दावा किया कि यह सामाजिक न्याय और समानता का विरोध करता है और सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की। फरवरी 2024 में, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने टिप्पणी की कि

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है , लेकिन उनका नहीं, जिसकी भाजपा नेताओं ने कड़ी निंदा की।

लोकसभा चुनाव में भाजपा और कॉग्रेस क चुनावी अभियान – भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान 16 और 17 जनवरी 2023 को आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास दोहराया और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया। आगामी चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति तैयार करते हुए, मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हाशिए पर पड़े और अल्पसंख्यक समुदायों सहित समाज के हर वर्ग तक ष्चुनावी हितों की परवाह किए बिना पहुंचना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद , मोदी ने 2024 के चुनावों के लिए ''मोदी की गारंटी'' का नारा पेश किया। इस चुनाव में एक प्रमुख नारा था ''अबकी बार 400 पार'', जो लोकसभा की 543 सीटों में से 400 से अधिक सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य को दर्शाता है।[16] भाजपा द्वारा पिछले चुनावों में, जिनमें 2019 का आम चुनाव भी शामिल है। कुछ बदलावों के साथ इसका इस्तेमाल किया गया है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा के लिए इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता संभवतः पिछले चुनावों की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक सीटें जीतना होगा।

भाजपा ने कई राज्यों में राजनीतिक रैलियां आयोजित कीं, जिनमें मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह सहित राष्ट्रीय नेतृत्व ने सक्रिय रूप से प्रचार किया। एक चुनावी रैली के दौरान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को ''राम भक्तों'' और ''राम विरोधी ताकतों'' के बीच का मुकाबला बताया और मतदाताओं से पूर्व को चुनने का आग्रह किया।[17] मोदी ने विपक्ष पर सत्ता में आने के बाद राम मंदिर को ध्वस्त करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। 21 अप्रैल को राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय संपदा में मुसलमानों की पहुँच को प्राथमिकता देने और सत्ता में आने के बाद संसाधनों को अधिक बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बाँटने की योजना बनाने का आरोप लगाया। यह आरोप मुसलमानों की अधिक संख्या में प्रजनन करने की रूढ़ियों और भाजपा द्वारा प्रचारित उन षड्यंत्र सिद्धांतों को दर्शाता है कि मुसलमान हिंदुओं से अधिक होने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गे ने मोदी की टिप्पणियों को दहशत से भरा ''घृणास्पद भाषण'' और चुनाव के पहले चरण में भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विपक्ष से ध्यान हटाने की एक चाल बताया। वहीं, राजस्थान के अधिकारियों को आज़ाद अधिकार सेना और एक गैर–लाभकारी संगठन से मोदी की गिरफ्तारी और उनके चुनाव प्रचार को निलंबित करने की मांग वाली शिकायतें मिलीं। मोदी के भाषण के बाद, भाजपा ने अपने

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मोदी के दावों को दोहराया गया और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र की एक प्रति पकड़े हुए दिखाया गया, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रतीक में बदल जाता है। कई उपयोगकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद, वीडियो को प्रकाशन के 24 घंटे से भी कम समय में हटा दिया गया। कर्नाटक में मतदाताओं के प्रति पर पोस्ट किए गए इसी तरह के एक वीडियो को भी चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश दिया था और इसके चलते पुलिस ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए। संविधान बचाओ नागरिक अभियान संगठन द्वारा भारत के चुनाव आयोग को लिखे गए एक शिकायत पत्र पर 17,400 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी ने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसका उद्देश्य न केवल ''सांप्रदायिक भावनाओं'' को भड़काना था, बल्कि हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति घृणा को उकसाना और बढ़ाना भी था।[18] 14 अप्रैल 2024 को, भाजपा ने देश में तैनात विदेशी राजनयिकों के साथ–साथ यूनाइटेड किंगडम की कंज़र्वेटिव और लेबर पार्टियों, जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) और जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी), और बांग्लादेश की अवामी लीग सहित 25 विदेशी राजनीतिक दलों को पार्टी के चुनावी अभियान का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। यह पहल ''बीजेपी को जानो'' अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य बाहरी संपर्क स्थापित करना और चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराना था।[19] इस कार्यक्रम के तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 13 देशों के दूतों से मुलाकात की।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) ब्लॉक की पहली संयुक्त रैली 3 मार्च 2024 को बिहार के पटना में आयोजित की गई। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, पार्टी नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव , समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी और डी. राजा सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। खर्गे ने कुमार पर बार–बार गठबंधन बदलने का आरोप लगाया और भाजपा की नौकरियों के वादे को पूरा न करने और देश के गरीबों और बहुसंख्यकों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के एक दिन बाद, 17 मार्च को गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क में संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया। रैली में गांधी, एसएस (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। रैली में गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने के लिए विवश होना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

केजरीवाल की 22 मार्च को कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, विपक्षी गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इसके विरोध में एक रैली आयोजित की, जहां विपक्षी नेताओं ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के मामले और उनकी बाद की गिरफ्तारी को ''राजनीतिक उद्देश्यों से रची गई साजिश'' और ''चुड़ैल का शिकार'' बताया।[20] ''लोकतंत्र बचाओ'' नाम की इस रैली में, मौजूदा घटनाओं के बीच, विपक्ष ने चुनाव को ''लोकतंत्र बनाम तानाशाही'' के रूप में पेश करने की कोशिश की।[21]

लोकसभा चुनाव 2024 के जनमत सर्वेक्षण और सीट प्रक्षेपण

तालिका

(क) जनमत सर्वेक्षण

मतदान एजेंसी	प्रकाशन तिथि	नमूने का आकार	त्रुटि के मार्जिन	एनडीए	भारत	अन्य	नेतृत्व करना
2024 चुनाव परिणाम				**43.8%**	**41.48%**	**14.72%**	**2.32**
एबीपी न्यूज़ – सीवीओटर	अप्रैल 2024[213]	57,566	±3-5%	**46.6**	39.8	13.6	6.8
समाचार 18	मार्च 2024[214]	118,616	±4%	**48**	32	20	16
एबीपी न्यूज़ – सीवीओटर	मार्च 2024[215]	41,762[216]	±5%	**46**	39	15	7
टाइम्स नाउ – ईटीजी	मार्च 2024[217]	323,357[218]	±3%	**52**	42	6	10
ज़ी न्यूज़ –मैट्रिज	फरवरी 2024[219]	167,843	±2%	**43.6**	27.7	24.9	15.9
इंडिया टुडे – सीवोटर	फरवरी 2024[220]	149,092[221]	±3-5%	**45**	38	17	8
टाइम्स नाउ – ईटीजी	फरवरी 2024[222]	156,843[223]	±2%	**41.8**	28.6	29.6	13.2
एबीपी न्यूज़ – सीवीओटर	दिसंबर 2023[224]	200,000	±3-5%	**42**	38	20	4
टाइम्स नाउ – ईटीजी	दिसंबर 2023[225][226]	147,231[227]	±3%	**44**	39	17	5
इंडिया टीवी – सीएनएक्स	अक्टूबर 2023[228][229]	54,250	±3%	**43.4**	39.1	17.5	4.3
टाइम्स नाउ – ईटीजी	अक्टूबर 2023[230]	135,100[231]	±3%	**42.6**	40.2	17.2	2.4
	अक्टूबर 2023[232][233]	110,662[234]	±3%	**42.6**	40.2	17.2	2.4
इंडिया टुडे – सीवोटर	अगस्त 2023[235]	160,438	±3-5%	**43**	41	16	2
भारत नामक विशाल विपक्षी गुट का गठन							
इंडिया टुडे – सीवोटर	ज्नवरी 2023[236]	140,917	±3-5%	**43**	30	27	13
2019 के चुनाव परिणाम				**45.3%**	**27.5%**	**27.2%**	**17.8**

स्रोत[22] : http//eci.gov.in

तालिका

(ख) सीट प्रक्षेपण

मतदान एजेंसी	प्रकाशन तिथि	नमूने का आकार	त्रुटि के मार्जिन	एनडीए	भारत	अन्य	नेतृत्व करना
2024 चुनाव परिणाम				**293**	**234**	**16**	**एनडीए**
TV9 भारतवर्ष–पीपल्स इनसाइट–पोल्स्ट्रैट	अप्रैल 2024[237]	2,500,000	3%	**362**	149	32	**एनडीए**
एबीपी न्यूज़ – सीवीओटर	अप्रैल 2024[213]	57,566	±3-5%	**373**	155	15	**एनडीए**
टाइम्स नाउ – ईटीजी	अप्रैल 2024[238]	271,292[239]	±3%	**384**	118	41	**एनडीए**
न्यूज 18	मार्च 2024[240]	118,616[241]	±4%	**411**	105	27	**एनडीए**
एबीपी न्यूज़ – सीवीओटर	मार्च 2024[242]	41,762	±5%	**366**	156	21	**एनडीए**

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

इंडिया टीवी – सीएनएक्स	मार्च 2024[243]	162,900[244]	±3%	**378**	98	67	**एनडीए**
टाइम्स नाउ – ईटीजी	मार्च 2024[245]	323,357	±3%	**358-398**	110-130	40-50	**एनडीए**
ज़ी न्यूज़ –मैट्रिज	फरवरी 2024[219]	167,843	±2%	**377**	93	73	**एनडीए**
इंडिया टुडे – सीवोटर	फरवरी 2024[246]	149,092[247]	±3-5%	**335**	166	42	**एनडीए**
टाइम्स नाउ – ईटीजी	फरवरी 2024[248]	156,843	±2%	**366**	104	73	**एनडीए**
एबीपी न्यूज़ – सीवीओटर	दिसंबर 2023[224]	200,000	±3-5%	**295-335**	165-205	35-65	**एनडीए**
टाइम्स नाउ – ईटीजी	दिसंबर 2023[225] [226]	147,231	±3%	**319-339**	148-168	52-61	**एनडीए**
इंडिया टीवी – सीएनएक्स	अक्टूबर 2023[228] [229]	54,250	±3%	**315**	172	56	**एनडीए**
टाइम्स नाउ – ईटीजी	अक्टूबर 2023[230]	135,100	±3%	**297-317**	165-185	57-65	**एनडीए**
	अक्टूबर 2023[249] [233]	110,662	±3%	**296-326**	160-190	56-64	**एनडीए**
इंडिया टुडे – सीवोटर	अगस्त 2023[235]	160,438	±3-5%	**306**	193	54	**एनडीए**
भारत नामक विशाल विपक्षी गुट का गठन							
इंडिया टुडे – सीवोटर	जनवरी 2023[250]	140,917	±3-5%	**298**	153	92	13
2019 के चुनाव परिणाम				**353**	**91**	**99**	**एनडीए**

स्रोत[23] : http//eci.gov.in

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा एवं गठबंधन को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण – लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा (भाजपा) को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने और कई राज्यों में राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन के पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक कारण रहे। प्रमुख कारणों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है[24] –

(क) **सत्ता विरोधी लहर (एंटी इनकम्बेन्सी)** – लगातार 10 वर्षों की केंद्र सरकार के बाद आम मतदाताओं में असंतोष कस रहा। महंगाई, बेरोज़गारी, किसान समस्याएँ जैसे मुद्दों पर नाराज़गी थी। कई सांसदों और मंत्रियों के प्रति स्थानीय स्तर पर असंतोष थी।

(ख) विपक्ष का प्रभावी गठबंधन (इंडिया गठबंधन) अपने रणनीतियां में सफल हुआ। कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय दलों का एकजुट होना। सीट बँटवारे से वोटों का बिखराव कम हो गए थे। भाजपा के विरुद्ध ''संविधान बचाओ'' और ''लोकतंत्र खतरे में'' जैसे नैरेटिव का असर बना रहा।

(ग) बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे प्रभावी रहे। युवाओं में रोजगार को लेकर गहरी चिंता थी। खाद्य पदार्थों, गैस, पेट्रोल–डीजल की कीमतों का प्रभाव रहा। आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार रहित विकास की धारणा सफल नहीं हुई।

(घ) ग्रामीण और किसान असंतोष कायम था। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी नहीं मिली थी। कृषि आय में स्थिरता का अभाव था। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कुछ राज्यों में किसान आन्दोलनों का चुनाव पर प्रभाव पड़ा।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

(ङ) सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा कायम रहा। जाति जनगणना की माँग को लेकर विपक्ष का आक्रामक रुख प्रभावी हुआ। दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों में भाजपा से आंशिक दूरी बनाये रखा। सामाजिक न्याय की राजनीति का पुनरुत्थान हुई।

(च) स्थानीय नेतृत्व और टिकट वितरण कार्य सफल नहीं हुआ। कई सीटों पर स्थानीय उम्मीदवारों का कमजोर चयन किया गया। पुराने और विवादित चेहरों को टिकट देने से नुकसान हुआ। क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी की गई।

(छ) भाजपा की ''400 पार'' का नारा और अति–आत्मविश्वास उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। **''400 पार'' के नारे से कुछ वर्गों में डर पैदा हुआ कि** संविधान में बदलाव हो सकता है। आरक्षण और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असर पड़ेगा।

(ज) कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों की मजबूती देखी गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का मजबूत जनाधार विकसित हुआ इसमें भाजपा का विस्तार सीमित रहा।

निष्कर्ष :– लोकसभा चुनाव (2024) के कार्यक्रम और परिणाम विगत लोकसभा चुनावों (2014 और 2019) की अपेक्षा बिलकुल अलग हुए। 18वीं लोकसभा चुनाव के मुद्दे एवं उभरती प्रवृत्तियों ने भारतीय मतदाताओं को विशेष रूप से प्रभावित किया। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा एवं गठबंधन ने लगातार अपना दायरा विकसित किया वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इसका दायरा सीमित हो गया। फिर भी इस चुनाव के पूर्ण बहुमत न मिलने पर भी केन्द्र में गठबंधन की सरकार बनायी। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केन्द्र में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद वर्तमान में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एवं गठबंधन की सरकार बनी है।

संदर्भ सुची :–

1. http//pib.gov.in
2. ई पेपर प्रभात खबर, 5 जून, 2024 राँची, झारखण्ड
3. ई पेपर प्रभात खबर, 5 जून, 2024 राँची, झारखण्ड
4. http//eci.gov.in
5. ई पेपर हिन्दुस्तान, 17 मार्च, 2024, राँची, झारखण्ड
6. www.ndtv.com/ 28 march, 2024

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

7. www.bbc.com/ 22 april, 2024
8. www.bbc.com/ 22 april, 2024
9. ई पेपर प्रभात खबर, 21 मार्च, 2024 राँची, झारखण्ड
10. ई पेपर हिन्दुस्तान, 15 मार्च, 2024, राँची, झारखण्ड
11. ई पेपर हिन्दुस्तान, 21 मार्च, 2024, राँची, झारखण्ड
12. ई पेपर हिन्दुस्तान, 28 मार्च, 2024, राँची, झारखण्ड
13. ई पेपर प्रभात खबर, 29 मार्च, 2024 राँची, झारखण्ड
14. ई पेपर द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 मार्च, 2024 नई दिल्ली
15. ई पेपर द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 3 सितम्बर, 2023 नई दिल्ली
16. ई पेपर द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 26 जुलाई, 2024 नई दिल्ली
17. ई पेपर हिन्दुस्तान, 25 जनवरी, 2024, राँची, झारखण्ड
18. ई पेपर हिन्दुस्तान, 23 अप्रैल, 2024, राँची, झारखण्ड
19. ई पेपर प्रभात खबर, 11 अप्रैल, 2024 राँची, झारखण्ड
20. ई पेपर प्रभात खबर, 31 मार्च, 2024 राँची, झारखण्ड
21. ई पेपर प्रभात खबर, 31 मार्च, 2024 राँची, झारखण्ड
22. http//eci.gov.in/
23. http//eci.gov.in/
24. ई पेपर प्रभात खबर, 5 जून, 2024 राँची, झारखण्ड